ई संदेश

30 जुलाई, 2026 | अंक - 216

सात दिन, सात पृष्ठ

- गोरखपुर में विकास और विरासत का नया युग:14 विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण तथा शिलान्यास
- स्मार्ट, सेफ और फ्यूचर रेडी बनता आगरा : मिली 53 परियोजनाओं की सौगात
- फतेहपुर में विकास और रोजगार का युग : 489 करोड़ से मिली नई उड़ान
- विकास पथ पर अग्रसर जालौन के नए अध्याय में जुड़ीं 1,274 करोड़ की 374 परियोजनाएं
- रोप-वे और बेहतरीन सुविधाओं से संवरेगा वृन्दावन
- स्वस्थ रहे शिक्षक परिवार : शिक्षकों के लिए शुरू हुयी "मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना"
- 682 करोड़ की सौगात से विकास के शीर्ष पर कदम बढ़ाता मैनपुरी
- विकसित उत्तर प्रदेश के अभियान में 604 करोड़ की सौगात ने इटावा की बढ़ाई चमक
- अधिवक्ता कल्याण और सुलभ न्याय प्रणाली के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में विकास और विरासत का नया युग:14 विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण तथा शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 23 जुलाई, 2026 को गोरखपुर में 995 करोड़ रुपये से अधिक की 14 विकास परियोजनाओं का ऐतिहासिक लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विकास और विरासत का सम्मान करते हुए बिना भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है।

मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में बताया कि आज प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से गोरखपुर से लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर की दूरी अब बहुत कम समय में तय की जा रही है। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि जहाँ कभी इन्सेफेलाइटिस और माफियाओं का आतंक था, वहाँ अब एम्स जैसे संस्थानों से बीमारियों का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है और रामगढ़ताल जैसा क्षेत्र आज पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है।

युवाओं के भविष्य पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीडा में नए उद्योगों की स्थापना से 50 हजार युवाओं को रोजगार मिला है। विगत नौ वर्षों में प्रदेश के 9 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गईं। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के माध्यम से परंपरागत उद्योगों को नया जीवन मिला है, जिससे प्रदेश का युवा और कारीगर आर्थिक रूप से अत्यंत सशक्त हुआ है।

अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी ने नागरिकों को विशेष निर्देश देते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़कर वृक्षारोपण करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने, घर का कूड़ा कलेक्शन गाड़ी को देने और जल संचयन करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सक्रियता और जागरूकता ही विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी।

स्मार्ट, सेफ और फ्यूचर रेडी बनता आगरा : मिली 53 परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 25 जुलाई, 2026 को आगरा में 342 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार आगरा को 'स्मार्ट सिटी', 'सेफ सिटी' और 'फ्यूचर रेडी सिटी' के रूप में तीव्रता से विकसित कर रही है।

अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ताज ट्रैपेजियम जोन (टी०टी०जेड०) के कारण लम्बित 468 औद्योगिक इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। इससे आगरा में नए उद्योगों की स्थापना का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं से यह क्षेत्र पर्यटन व उद्योग का नया वैश्विक केंद्र बन रहा है।

नागरिक सुविधाओं और कृषि विकास पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि ग्रेटर आगरा हेतु 5,200 करोड़ रुपये की टाउनशिप योजनाओं और 1,500 करोड़ से अटलपुरम टाउनशिप को स्वीकृति दी गई है। वहीं, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना से किसानों के उत्पादों को वैल्यू एडिशन मिलेगा, जिससे उनकी आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

विरासत के संरक्षण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भव्य संग्रहालय का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 500 कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व की सरकारों की तुलना में आज का उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त और पूरी तरह सुरक्षित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बिना थके, समाज के हर तबके के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि विगत नौ वर्षों में नौ लाख युवाओं को बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

फतेहपुर में विकास और रोजगार का युग : 489 करोड़ से मिली नई उड़ान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 25 जुलाई, 2026 को जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि इन वृहद परियोजनाओं के माध्यम से फतेहपुर आकांक्षी जनपद की श्रेणी से बाहर निकलकर विकसित जनपदों की सूची में अपना स्थान पक्का कर चुका है।

युवाओं के सुरक्षित भविष्य पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परीक्षाओं में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नकल माफियाओं के विरुद्ध अत्यंत कठोर निर्णय लिए गए, जिसके तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष की कड़ी सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप ही विगत नौ वर्षों में प्रदेश के नौ लाख से अधिक युवाओं को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त हुईं।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम सम्बोधन में कहा कि अन्नदाता किसानों के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी।किसानों के निजी नलकूपों के 3,000 करोड़ रुपये के विद्युत बिल का सम्पूर्ण भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से किसान व सह-किसान परिवारों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता सुनिश्चित कर उन्हें एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया।

बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जनपद में मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ नए नर्सिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की गई। इससे स्थानीय युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिला। सरकार के इन निरंतर प्रयासों से जनपद के सर्वांगीण विकास को एक नई और सशक्त दिशा प्राप्त हुई।

विकास पथ पर अग्रसर जालौन के नए अध्याय में जुड़ीं 1,274 करोड़ की 374 परियोजनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 25 जुलाई, 2026 को जनपद जालौन के उरई, माधौगढ़ एवं कालपी विधान सभा क्षेत्रों के लिए 1,274 करोड़ रुपये की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, टूलकिट एवं आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए।

बुंदेलखंड के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि कभी सूखा और बीहड़ के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र अब विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। यह क्षेत्र अब देश के सबसे बड़े औद्योगिक टाउनशिप 'बीडा' और पहले सोलर एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

युवाओं के सुरक्षित भविष्य को प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कड़े निर्देश दिए गए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में शुचिता बनाए रखने हेतु दोषियों के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराध और माफिया तंत्र की संपत्तियां निरंतर जब्त की जा रही हैं।

सरकार की पारदर्शी नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में महिला सुरक्षा सुदृढ़ हुई है और बेटियां भयमुक्त होकर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत कालपी के हस्तनिर्मित कागज को जीआई टैग मिलने से इसे वैश्विक पहचान मिली है। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सीधे डीबीटी द्वारा करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में निर्बाध पेंशन पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि जालौन सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र, संतुलित और तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

रोप-वे और बेहतरीन सुविधाओं से संवरेगा वृन्दावन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 25 जुलाई, 2026 को जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने वृन्दावन और मथुरा के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए इसके समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को वृन्दावन में रोप-वे परियोजना और मथुरा-वृन्दावन रेल मार्ग पर सड़क-रेल संयुक्त प्रस्ताव को शीघ्र शासन को भेजने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पीपीपी मॉडल पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था विकसित करने हेतु लैंड पूलिंग योजना को भी तत्काल गति देने को कहा।

स्वच्छता को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए, मुख्यमंत्री जी ने मथुरा-वृन्दावन में चल रहे स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन-जागरूकता और प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की मदद से दोनों पवित्र नगरों को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। इसके साथ ही, पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और 'तीर्थ-मित्र' नीति का शासनादेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए।

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक नया वृन्दावन पुलिस सर्किल बनाने, एएसपी यातायात व एएसपी प्रोटोकॉल के नए पद सृजित करने और फ्लोटिंग आबादी के आधार पर मानव संसाधन बढ़ाने के प्रस्तावों पर अपनी तत्काल सहमति दी।

बैठक में मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई महायोजना के प्रस्तावित मार्ग यातायात व्यवस्था/अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य चौराहों के इम्प्रूवमेंट कार्य और फ्लाईओवर व मार्ग के सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने इस कार्ययोजना की गहन समीक्षा की, साथ ही, यमुना पार की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

स्वस्थ रहे शिक्षक परिवार : शिक्षकों के लिए शुरू हुयी "मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 जुलाई, 2026 को आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के 7.50 लाख से अधिक शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारम्भ किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लगभग 10 लाख सदस्य लाभान्वित हुए। राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग तथा पंजाब नेशनल बैंक के मध्य एक महत्वपूर्ण एमओयू का निष्पादन किया। इसके तहत दुर्घटना की अप्रत्याशित स्थिति में शिक्षक के परिवार को 1.5 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा तथा अन्य नकद लाभ की व्यवस्था की।

समारोह में राष्ट्र निर्माण में गुरुओं की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्राचीन भारत के तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराया। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को अनुशासन और 'राष्ट्र प्रथम' के भाव से जोड़ें। मुख्यमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को किसी भी प्रकार के भटकाव और नकारात्मकता से बचाने के लिए छात्रों को सही मार्गदर्शन और सन्मार्ग प्रदान करने पर विशेष बल दिया।

आधुनिक चुनौतियों और तकनीकी युग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के प्रति छात्रों को जागरूक करने की आवश्यकता बतायी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बिना प्रामाणिक जानकारी के सोशल मीडिया पर फैलने वाली अराजकता और विद्वेष से समाज को सुरक्षित रखने के लिए छात्रों में आत्म-अनुशासन विकसित करना अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रभक्ति तथा नवाचार के शोध केंद्र के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। साथ ही, भविष्य में स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों एवं विश्वविद्यालयों के 50 हजार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इस सुरक्षा आवरण में सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व बैंक से आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की।

एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत शिक्षक के परिवार को योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 1.5 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर, 03 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर, 60,000 रुपये तक का अस्पताल नकद लाभ, 12 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ बीमा कवर आदि लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।

682 करोड़ की सौगात से विकास के शीर्ष पर कदम बढ़ाता मैनपुरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 जुलाई, 2026 को जनपद मैनपुरी और करहल विधान सभा क्षेत्रों के लिए 682 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैनपुरी मयन और च्यवन ऋषि की ऐतिहासिक धरा है, जिसे डबल इंजन सरकार ने एक नई और सुरक्षित पहचान दिलाई है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टैबलेट, आवास की चाभी और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से उबरकर एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के फलस्वरूप 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं, जिनमें मैनपुरी और इटावा के युवाओं ने भी पूरी योग्यता के साथ स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के चार प्रमुख स्तंभों—गरीब, किसान, महिला और नौजवान—के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों के हित में 36,000 करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ किया गया तथा निजी नलकूपों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई गई। साथ ही, ओडीओपी योजना के तहत मैनपुरी की 'तारकशी' कला को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित किया गया।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी व्यापक परियोजनाएं क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आज का उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन चुका है, जहां कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी जैसे पर्व पूरे हर्षोल्लास व सुरक्षा के साथ मनाए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार विरासत, विकास और स्वावलंबन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विकसित उत्तर प्रदेश के अभियान में 604 करोड़ की सौगात ने इटावा की बढ़ाई चमक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 जुलाई, 2026 को जनपद इटावा में 604 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 128 विकास परियोजनाओं का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को टूलकिट, चेक और कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी प्रदान किये।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने इटावा सहित पूरे प्रदेश के नौजवानों को पहचान के संकट से उबारने का सफल कार्य किया है। उन्होंने बताया कि अब इटावा के नाम पर कहीं भय या दहशत नहीं है, बल्कि यहाँ के युवाओं को देश-प्रदेश में पूरा सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर पूरी सख्ती से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर रेवेन्यू सरप्लस राज्य और देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि अब प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' नहीं, बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' की गूंज है। आज प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, बल्कि हर तरफ उत्सव और उल्लास का माहौल है।

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के हर जनपद का समान विकास कर रही है। उन्होंने सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज, गंगा एक्सप्रेस-वे और जल जीवन मिशन जैसी अहम ढांचागत परियोजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली व सम्मान निधि और युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से रोजगार प्रदान कर, सरकार विकसित भारत के लिए एक 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है।

अधिवक्ता कल्याण और सुलभ न्याय प्रणाली के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 28 जुलाई, 2026 को गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह को सम्बोधित करते हुए न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दृढ़ता के साथ रेखांकित किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं, जो संविधान के प्रति पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इन स्तम्भों के बीच संवाद स्थापित करने और आम नागरिक तक समयबद्ध न्याय सहजता से पहुँचाने में अधिवक्ता समुदाय एक जागरूक प्रहरी की तरह अपना योगदान देता है।

गोरखपुर बार एसोसिएशन की 130 वर्षों की समृद्ध विरासत का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि देश के स्वाधीनता आन्दोलन से लेकर संविधान निर्माण तक में अधिवक्ताओं का सर्वोपरि योगदान रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. भीमराव आंबेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और पं. गोविन्द बल्लभ पंत जैसे महापुरुष अधिवक्ता ही थे। इसी गौरवशाली परम्परा को सम्मान देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसका शैक्षणिक सत्र भी सफलतापूर्वक प्रारम्भ हो चुका है।

अधिवक्ताओं की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की माँग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और शीघ्र ही एक व्यवस्था बनाकर इसे लागू किया जाएगा। अधिवक्ता कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर सीधे 05 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, सहायता के लिए अधिवक्ताओं की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। अधिवक्ता कल्याण निधि के कॉर्पस फण्ड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया गया है, जिसके माध्यम से अब तक 4,000 से अधिक आश्रितों को 200 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। युवा अधिवक्ताओं के बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकें व विधिक पत्रिकाएं क्रय करने के लिए भी 1.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी ऐतिहासिक वृद्धि सुनिश्चित की गई है। न्याय मित्र, विशेष अधिवक्ता और नामिका वकील की बहस फीस बढ़ाकर 2,300 रुपये कर दी गई है। उप जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस 9,000 रुपये, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की 10,000 रुपये, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की 11,000 रुपये तथा जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के विधि अधिकारियों की फीस में भी 50 प्रतिशत से अधिक की भारी वृद्धि की गई है।

प्रदेश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत झाँसी, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर निर्माण हेतु करोड़ों रुपये अवमुक्त किए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 2,500 एडवोकेट चैम्बर, मल्टीलेवल पार्किंग और लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने 10 जनपदों में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की प्रभावी पहल की है।

देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की सफलता में भी अधिवक्ताओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन कानूनों में सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य होने के दृष्टिगत, प्रदेश में 12 नई फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है और 6 निर्माणाधीन हैं। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की गई है। तकनीक के प्रयोग पर विशेष बल देते हुए ई-पुलिसिंग, ई-प्रॉसिक्यूशन और ई-फॉरेंसिक को इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कार्यवाही तेजी से संचालित है।

भारत के अभूतपूर्व विकास की चर्चा करते हुए यह तथ्य रखा गया कि आज देश दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय, 4 करोड़ आवास, 45 करोड़ जन धन खाते और 12 करोड़ निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के धरातल पर उतरी हैं। उत्तर प्रदेश भी अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति और बेहतरीन सड़क व एयर कनेक्टिविटी ने विकास की नई इबारत लिखी है, जिससे गोरखपुर के रामगढ़ताल जैसे क्षेत्रों का पूरा कायाकल्प हो गया है और प्रदेश में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर आ गई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने अधिवक्ता समाज का आह्वान करते हुए कहा कि जब भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब देश को कमजोर करने और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले षड्यंत्रों का डटकर मुकाबला करने के लिए, संविधान के सच्चे प्रहरी के रूप में अधिवक्ताओं को सदैव तत्पर रहना होगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित